

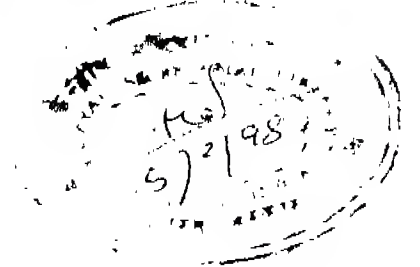


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 649]
No. 649]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1997/अग्रहायण 6, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1997/AGRAHAYANA 6, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1997

का. आ. 798(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण

अध्यक्ष : माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. के. मेहरा

नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)

के

संबंध में

न्यायाधिकरण की रिपोर्ट

17 सितम्बर, 1997

3017 GI/97

रिपोर्ट

भारत के राजपत्र §असाधारण§ में 3 अप्रैल, 1997 को नई दिल्ली में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 §1967 का 37§§ जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है§ की धारा 3 की उप-धारा §i§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा §जिसे इसमें इसके बाद "पन0पल0पफ0टी0" कहा गया है§ को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया गया है । उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :

का0आ0 292 §अ§ -- जबकि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा §इसके बाद इसे पन0पल0पफ0टी0 कहा गया है § का घोषित लक्ष्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगवादी संगठनों से समझौता करके सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत संघ से पृथक् कराकर एक स्वतंत्र बोरोकलैंड त्रिपुरा का निर्माण करना और त्रिपुरा के मूल निवासियों को अलगवादी के लिए उकसाना और उसके द्वारा त्रिपुरा का भारत संघ से अलग करना है,

जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि पन0पल0पफ0टी0 -

§i§ विध्वंसकारी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार की सत्ता को क्षति हो रही है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह लोगों में आतंक और हिंसा फैला रही है,

§ii§ ने अन्य गैरकानूनी संगठनों अर्थात् नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड §पन0पस0सी0पन0-1§ के इजाजत सू गुट से उनका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित किया है,

§iii§ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में अनेक हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ है जो भारत की प्रभुता और अखण्डता के प्रतिकूल है,

और जबकि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- §क§ नागरिकों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या,
- §ख§ त्रिपुरा में व्यवसायों तथा व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन पेंठना,
- §ग§ गुप्त/गैरकानूनी माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त करना और इन्हें किसी पड़ोसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में गुप्त रूप से भेजना,

§ प§ सुरक्षित पनाह, प्रशिक्षण, हथियारों तथा गोलाबारूद की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी पड़ोसी देश में शिविर लगाना और उनका संचालन करना,

§ ड-§ त्रिपुरा में जनजातीय तथा गैर-जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगे करवाने तथा भड़काने के लिए त्रिपुरा के अन्य जनजातीय उग्रवादी समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे बनाए रखना ।

और जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि एन०एल०एफ०टी० की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए खतरा है और यह एक गैरकानूनी संगठन है,

अतएव, अब गैरकानूनी गतिविधियां §निरोधक§ अधिनियम, 1967 §1967 का 37§ की धारा 3 की उपधारा §1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पत्रद्वारा घोषणा करती है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा §एन०एल०एफ०टी०§ एक गैरकानूनी संगम है,

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि एन०एल०एफ०टी० पर तत्काल नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्यों के लिए अवसर मिल जाएगा -

§ i§ अपने संगठनों को अलगाववादी, विघटनकारी और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए संगठित करना,

§ ii§ भारत की अखंडता व राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकार ताकतों के साथ संठ-गांठ करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुले तौर पर प्रचार करना,

§ iii§ नागरिकों और पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों को लक्ष्य बनाकर हत्या करने की बारदातों में अधिकाधिक शामिल होना,

§ iv§ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र व गोलाबारूद प्राप्त करना,

§ v§ अपनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी मात्रा में धनराशि रेंठना ।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का मत है कि पन०पल०पफ०वि० को तत्काल प्रभावी रूप से गैरकानूनी संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा 3 के पस्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्याधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

उक्त अधिसूचना का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 § 1§ के अंतर्गत 1.5.97 को एक अधिसूचना जारी कर इस ट्रिब्यूनल का गठन किया ताकि यह न्याय निर्णयन किया जा सके कि क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 3.4.1997 को जारी अधिसूचना द्वारा पन०पल०पफ०वि० को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। अधिनियम की धारा 5 § 1§ के अंतर्गत जारी दिनांक 1.5.97 की उक्त अधिसूचना इस प्रकार है :-

गृह मंत्रालय

§फा०सं० 9/27/97-पन०वि०-1§

§भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, धारा 3, उपधारा §ii§ में प्रकाशनार्ह §

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1997

का०आ० 362§अ§, -- केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 § 1967 का 37§ की धारा 5 की उपधारा §1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्याय निर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि अंत त्रिपुरा एडगर फोर्स §प०वि०प०पफ०वि०§ और नेशनल लिबरेशन फंड ऑफ त्रिपुरा §पन०पल०पफ०वि०§ को, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 3.4.1997 की अधिसूचना सं० का०आ० 291 §अ§ और 292 §अ§ द्वारा विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जा चुका है, विधि-विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, "विधि-

विरुद्ध क्रियाकलाप § निवारण § अधिकरण" गोठित करती है । अधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे०के० मेहरा से मिलकर बनेगा ।

जी०के० फिल्ले

§ जी०के० फिल्ले §

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

§ पन०पल०पफ०वे०-9/27/97-पन०ई०-1 §

इस ट्रिब्यूनल का गठन करके, पन०पल०पफ०वे० के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यकलापों का सार इस ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया है जिससे त्रिपुरा में विद्रोह की शुरुआत के संक्षिप्त इतिहास का पता चलता है । कहा गया है कि इस राज्य में जनजातीय / गैर जनजातीय तनाव का एक इतिहास रहा है । इसमें मुख्य रूप से बंगाली, त्रिपुरी, रिंग्स जमातिया और चकमा रहते हैं । कुल जनसंख्या के 31 प्रतिशत की जनसंख्या वाली जनजातियों में इस बात की शिकायत है कि पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से गैरजनजातियों के लगातार आब्रजन/घुसपैठ के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है । यह भी कहा गया है कि वर्तमान समय में त्रिपुरा की स्थिति जनजातीय आतंकवादियों / शरारती तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हिंसा द्वारा प्रभावित है । 1993 से ही उनकी अलगवादी , विघटनकारी और हिंसक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं । आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स § प०वे०वे०पफ० § और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा § पन०पल०पफ०वे० § अधिक सक्रिय हैं ।

सार में यह भी कहा गया है कि पन०पल०पफ०वे० का गठन त्रिपुरा नेशनल वालिण्टियर § पन०वी० § के कुछ स्वयं प्रत्यावर्तियों के साथ धर्मेन्द्ररियंग द्वारा 1989 में किया गया था । बाद में धर्मेन्द्ररियंग को पन०पल०पफ०वे० से निकाल दिया गया था । इस समय विश्वमोहन देवबर्मा इसके अध्यक्ष हैं । उक्त अधिनियम की धारा 5§1§ के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के गठन के तत्काल बाद विभिन्न समाचार पत्रों, जो त्रिपुरा राज्य में परिचालन में हैं, में प्रकाशन के ज़ोर

प्रतिबंधित संगठन, एन.एल.एफ.टी. को नोटिस तामील किए गए थे। इस नोटिस का आकाशवाणी, अगरतला रेडियो स्टेशन से भी प्रसार किया गया था। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने अपने-अपने शपथ पत्र दायर किए हैं जिसमें यह घोषणा की गई है कि नोटिस का अगरतला जिला, त्रिपुरा राज्य में पुलिस अधीक्षक के जरिए पुलिस द्वारा व्यापक प्रचार किए जाने के अलावा आकाशवाणी द्वारा विधिवत रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया था। हालांकि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा § 2§ के अंतर्गत यथा अपेक्षित कार्य कर दिया गया था, किंतु एन.एल.एफ.टी. की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। तथापि, त्रिपुरा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया था।

नोटिस तामील हो जाने के बारे में संतुष्ट हो जाने के पश्चात, मैंने मामले को अगरतला में राज्य सरकार का साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निर्धारित किया। राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध गतिविधियों के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। जांच की गई गवाहियों में अधिकांशतः त्रिपुरा राज्य के पुलिस अधिकारी थे। त्रिपुरा राज्य ने कुल पांच गवाहियां अर्थात् पी.डब्ल्यू. 1 से 4 तक और पी.डब्ल्यू. 6 पेश कीं। पी.डब्ल्यू. 1 से 4 तक की जांच अगरतला में की गई थी जबकि पी.डब्ल्यू. की जांच नई दिल्ली में की गई।

पी0डब्ल्यू0-1 ने कहा है कि उक्त संगठन जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के मध्य सौहार्द समाप्त करने और दुश्मनी बढ़ाने के प्रचार में संलग्न है। उक्त गवाह ने एक दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जिसको उक्त त्रिपुरा राज्य का कथित संविधान बताया जाता है और उसमें पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में बतौर साक्ष्य एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें एन0एल0एफ0टी0 के शरणास्थलों की अवस्थिति दर्शायी गई है। इन दस्तावेजों पर पुलिस के कथित हस्ताक्षर हैं। उसने पी.डब्ल्यू.-1/3 भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो एन0एल0एफ0टी0 द्वारा भेजा गया एक फिरौती नोट है और उसने पी.डब्ल्यू. 1/4 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जो एक चन्दा नोटिस है जिसमें नागरिकों से एन0एल0एफ0टी0 को चन्दा देने को कहा गया है। उक्त गवाह ने एन0एल0एफ0टी0 द्वारा जारी किए गए विभिन्न पत्र पी.डब्ल्यू. 1/5, पी.डब्ल्यू. 1/6, और पी.डब्ल्यू. 1/7 भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं जिनमें विभिन्न व्यक्तियों से राजस्व और कर की मांग की गई है। इन दस्तावेजों के अलावा उसने पी.डब्ल्यू. 1/9 चार्ट भी प्रस्तुत किया है जिसमें एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों के विरुद्ध पंजीकृत विभिन्न मामले दर्शाए गए हैं। बताया

जाता है कि यह चार्ट एन०एल०एफ०टी० उग्रवादियों के विरुद्ध पंजीकृत मामलों से संबंधित मूल वस्तुओं से तैयार किया गया है । एन०एल०एफ०टी० के संविधान में कहा गया है कि इस संगम का उद्देश्य "बोरोकलैंड त्रिपुरा" को आजाद कराने के पश्चात् त्रिपुरा की बोरोक संस्कृति को स्वतंत्र मान्यता दिलाना है । "बोरो" का संबंध त्रिपुरा के स्थानीय लोगों से है । पी०डब्ल्यू० 2 में साक्ष्य के रूप में वे विभिन्न एफ०आई०आर० प्रस्तुत किए गए हैं जो उग्रवादियों द्वारा किए गए कथित अपराधों के कारण उनके विरुद्ध त्रिपुरा राज्य के थानों में पंजीकृत हैं । पी०डब्ल्यू० 3 में साक्ष्य के रूप में भारी संख्या में हथियारों और गोला बारूदों का जन्त करना दिखाया गया है । उक्त जन्ती ज्ञापन पी०डब्ल्यू० 3/8 है । पी०डब्ल्यू० 3/2 प्रथम बयोलियन टी०एस०आर० के कमान्डेंट को एन०एल०एफ०टी० द्वारा जारी पत्र की छाया प्रति है जिसमें उसको द्विपुरा के बोरोक लोगों के साथ दंग से पेश आने की घमकी दी गई है । पी०डब्ल्यू० 3/3 राजस्व और कर संग्रहण के लिए प्राप्त नोटिस है । पी०डब्ल्यू० 3/4 और पी०डब्ल्यू०, डाइविंग लाइसेंस तलाशी के दौरान पकड़े गए थे । पी०डब्ल्यू० 4 में कहा गया है कि एन०एल०एफ०टी० को कुछ जनजातीय और गैर-जनजातीय अपराधी और उग्रवादी समूहों का भी समर्थन प्राप्त है । उनकी भूमिका शरण देने और सहयोग करने वालों की है । उसमें यह भी कहा है कि एन०एल०एफ०टी० के एन०एस०सी०एन० §आई०§ समूह के साथ कुछ संबंध है । उसके अनुसार बंगलादेश में एन०एल०एफ०टी० के प्रशिक्षण शिविर और शरणास्थल हैं । उसने यह भी कहा है कि एन०एल०एफ०टी० ने निर्दोष लोगों की हत्याएं करने, नागरिकों पर अत्याचार करके भय का राज्य स्थापित करने की कोशिश की है ताकि आम जनता उनसे अपनी मत विभिन्नता को जाहिर न कर सके और उक्त संगम में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का भी प्रयास किया है ।

पी०डब्ल्यू० 6 से नई दिल्ली में पूछताछ की गई थी । उसने एक शपथ पत्र दायर किया था तथा सुनवाई के समय उसके तर्कों को सिद्ध किया था । उसने अपने शपथ पत्र पी०डब्ल्यू० 6/1 में बताया था कि उनके पृथक्तावादी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के भाग के रूप में एन०एल०एफ०टी० ने एक अलग संविधान तैयार किया था जिसमें नागरिक दंगे के साज-सामान के साथ एक अलग "जनगणतंत्र सरकार" की व्यवस्था की गई थी । उसने यह भी बताया है कि एन०एल०एफ०टी० अनेक विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहा है जिनमें अर्द्ध सैनिक बलों तथा पुलिस कार्मिकों से शस्त्र एवं गोला बारूद छीनने जैसी हिंसक घटनाएं शामिल हैं जिनमें अनेक अर्द्ध सैनिक एवं

पुलिस कार्मिकों तथा नागरिकों ने अपनी जाने गवाई हैं । इसके अतिरिक्त शस्त्रों एवं गोला बारूद जुटाने के लिए तथा अपने नेताओं व संघर्षों के रख-रखाव के लिए धन पेंठने तथा धन के अवैध संग्रहण का सहारा लेता रहा है । पूर्वोत्तर में अन्य विद्रोही संगठनों को प्रेरणा एवं समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना एन.एल.एफ.टी. का उद्देश्य रहा है तथा यह कि इसके नागालैंड की एन0एस0सी0एन0॥आई॥ के साथ संबंध है ।

केन्द्र सरकार की ओर से केवल एक गवाह अर्थात् पी.डब्ल्यू. 5 से कलकत्ता में पूछताछ की गई थी-तथा उसने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र दायर किया है जिसमें उसने अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त उक्त दस्तावेज जो कि एन0एल0एफ0टी0 के संविधान से संबंधित है जो कि पी.डब्ल्यू. 5/1ए है जिसे गवाह पी.डब्ल्यू. 5 प्रस्तुत किया गया था/जिससे यह प्रतीत होता है कि एन0एल0एफ0टी0 का उद्देश्य बोरोकलैंड त्रिपुरा को आजाद कराने के बाद त्रिपुरा की बोरोक सभ्यता की स्वतंत्र पहचान बनाना है । पी.डब्ल्यू. 5/1 बी, जो त्रिपुरा राज्य द्वारा केन्द्र सरकार को किया गया पत्राचार है, से स्पष्ट है कि विश्व मोहन देवबर्मा की अध्यक्षता वाले एन0एल0एफ0टी0 की स्वयंभू गृह मंत्री और सेनाध्यक्ष कामिनी देवबर्मा हैं । इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम त्रिपुरा, दलाई, उत्तरी और दक्षिणी त्रिपुरा जिले आते हैं । त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार एन0एल0एफ0टी0 के पास बारह ए0के0-56 राइफलें, एक एल.एम.जी., 8 एस.एल.आर., 22, 303-राइफलें, 1 स्टेनगन, 2 पिस्तौल, 5 रिबॉल्वर और 1 कार्बाइन हैं ।

रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह सिद्ध होता है कि भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की विरोधी ताकतों के सहयोग से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करने के अलावा एन.एल.एफ.टी. अलगाववादी, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है । उक्त संगठन नागरिकों की हत्याओं, लूटपाट, छीनाछपट, आपराधिक कार्य और कानून विहीनता का वातावरण बनाने में संलिप्त है ।

उक्त अधिनियम में धारा 2॥च॥ में "विधि विरुद्ध गतिविधि" और धारा 2 ॥छ॥ में "विधि विरुद्ध संगम" की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं :-

॥च॥ किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में "विधि विरुद्ध गतिविधि" का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा की गई कोई ऐसी कार्रवाई से है ॥कोई कार्य करके या बोले गये या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या प्रकट कार्यकलापों या अन्य प्रकार से॥

§ i § जो भारतीय क्षेत्र के किसी भाग के अलगाव या भारत संघ से उनके किसी भाग के अलगाव का किसी भी आधार पर ह्छुक है या समर्थन करता है अथवा जो ऐसे अलगाव के लिए व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उकसाता है,

§ ii § जो भारत की सम्प्रभुता एवं भूभागीय अखण्डता को नहीं मानता है, सवाल उठाता है, छिन्न-भिन्न करता है या छिन्न-भिन्न करना चाहता है,"

§ iii § "विधिविरुद्ध संगम" का अर्थ है - ऐसा संगम जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विधिविरुद्ध कार्य करता है, या जो विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों को उकसाता या उनकी मदद करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसे कार्य करते रहते हैं ।"

रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारता की वलीलों से यह सिद्ध होता है कि एन.एल.एफ.टी. विध्वंसक, अलगाववादी व हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है और उक्त संगम ने दूसरे विधिविरुद्ध संगमों से भी अपने संपर्क बनाये हैं । यह भी सिद्ध होता है कि एन.एल.एफ.टी. नागरिकों और पुलिस बलों के कार्मिकों की हत्याओं और अवैध माध्यमों से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने तथा उनको एक पड़ोसी देश के रास्ते गुप्त ढंग से त्रिपुरा लाने के लिए त्रिपुरा की जनता एवं व्यापारियों से धन पेंठने के कार्य करती रही है । उक्त संगम का उद्देश्य एवं लक्ष्य भारत से अलग होना तथा एन.एल.एफ.टी. का एक सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य स्थापित करना है ।

रिकार्ड से यह भी सिद्ध होता है कि यदि उक्त गतिविधियां जारी रखने की एन.एल.एफ.टी. को अनुमति दी जाती रही तो इसका अर्थ होगा उसकी विद्रोही एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों को समर्थन देना । प्रत्येक एफ.आई.आर. या शपथ में रिकार्ड किए गए प्रत्येक हलफनामों पर पूर्णतः विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कार्यवाही रिकार्ड का ही भाग हैं ।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह सिद्ध हो जाता है कि एन.एल.एफ.टी. विभिन्न हिंसक गतिविधियों में और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जिनसे भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के छिन्न-भिन्न होने का खतरा है । यह भी सिद्ध होता है कि समय बीतने के साथ-साथ

सेवा में,

विधिविरुद्ध गतिविधियां बढ़ती जाएंगी और एन.एल.एफ.टी. अलगाववाद की वकालत करता रहा है और अलगाववादी नीतियां अपना रहा है जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(च) में परिभाषितानुसार विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को बढ़ाती है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं संतुष्ट हूँ कि एन.एल.एफ.टी. को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं। परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3-4-97 की अधिसूचना के द्वारा घोषणा की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

दिनांक 17 सितम्बर, 1997

(जे. के. मेहरा)

मंत्रिगण

ट्रिब्यूनल

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) न्यायाधिकरण

नई दिल्ली।

[फा. सं. 9/27/97-एन ई-1]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1997

S.O. 798(E).—The following is published for general information :—

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

HEADED BY HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MEHRA

IN THE MATTER OF

NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA (NLFT)

REPORT OF THE TRIBUNAL

17th September, 1997

REPORT

By a Notification of Ministry of Home Affairs published at New Delhi on 3rd April, 1997 in the Gazette of India (Extraordinary), the Central Government in the exercise of its powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as "the said Act"), declared National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as "NLFT") as an unlawful association. The said Notification reads as under :—

S.O. 292(E).—Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as NLFT) has its professed aim to establish an independent "Borokland Twipra" by liberation of Tripura from the Indian Union through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from the Indian Union :

And whereas the Central Government is of the opinion that NLFT has—

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the lawfully established Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective :

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the Isak Swu faction of National Socialist Council of Nagaland (NSCN-IM) with the aim of mobilising their support ;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India:

And whereas the Central Government is also of the opinion that violent and unlawful activities include—

(a) Killing of civilians and personnel belonging to the Police Security Forces :

(b) Extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura :

(c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition, etc.;

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) as an unlawful association :

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT will take the opportunity to—

(i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(ii) Propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targetting of Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for its activities.

Having regard to the above circumstances, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the NLFT as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section 3 of the said section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the official gazette."

Following the said Notification, Government of India issued a Notification dated 1-5-97 under section 5(1) of the said Act constituting this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the NLFT as

unlawful association declared as such by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S. O. 292(E) dated 3-4-1997. The said Notification dated 1-5-97 issued under Section 5(1) of the Act reads as under :—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(F. NO. 9/27/97-NE.1)

(To be Published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 1st May, 1997

S.O. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the “Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force (ATTF) and National Liberation Front of Tripura (NLFT) as unlawful associations declared as such by the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S. O. 291(E) and 292(E) dated 3-4-1997 respectively. The Tribunal shall consist of Mr. Justice J. K. Mehra Judge of the Delhi High Court.

Sd/-

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

(F. No. 9/27/97-NE. I")

With the constitution of this Tribunal, the resume on the aims, objectives and activities of NLFT has also been filed before this Tribunal which gives brief history of the origin of the insurgency in the State of Tripura. It is stated that the State, which has a history of tribal/non-tribal tension, is mainly inhabited by Bengalis, Tripuris, Reangs, Jamatias and the Chakmas. The tribals, who comprise approximately 31% of the total population, harbour a grievance of being overwhelmed by non-tribals through successive waves of migration/infiltration from neighbouring East Pakistan/Bangladesh. It is further mentioned that currently in Tripura the situation is affected by a high level of violence by tribal extremists/miscreants. Their secessionist, subversive and violent activities have been on the increase since 1993. The All Tripura Tiger Force (ATTF) and the National Liberation Front of Tripura (NLFT) are the most active.

It is further submitted in the resume that the NLFT was formed in 1989 by Dhananjay Reang alongwith some disgruntled Tripura National Volunteers (NV) returnees. Subsequently Dhananjay Reang was ousted from the NLFT which is currently headed by Biswa Mohan Debbarma. Immediately on being constituted the Tribunal under Section 5(1) of the said Act, notices were served upon the NLFT, the banned organisation by way of publication in various newspapers which are in circulation in the State of Tripura. The notice was also broadcast by the AIR from Agartala Radio Station. Central Government and State Government have filed their respective affidavits declaring that the notices were duly published and broadcast by AIR in addition to wide publicity to notice by Police through Superintendent of Police in the District of Agartala, State of Tripura. Although service was effected as required under sub-section (2) of Section 4 of the Act, no one put in appearance on behalf of NLFT. The State of Tripura and Central Government were, however, represented.

After feeling satisfied about service of notices, I fixed the case for recording evidence of the State Government at Agartala. Documentary as well as oral evidence has been produced by the State Government in proof of the activities listed in the aforesaid notification. Most of the witnesses examined were the police officers from the State of Tripura. State of Tripura produced in all five witnesses being P.W. 1 to 4 and P.W. 6. P.W. 1 to 4 were examined at Agartala, while P.W. 6 was examined at New Delhi.

P.W. 1 has stated that the said organisation is spreading propaganda with a view to spread disharmony and bad blood between the tribals and non-tribals. The said witness also proved a document which purports to be constitution alleged to be of the said State of Tripura and he also proved the map as exhibit PW/2 showing the location of the hideouts of NLFT. These documents were alleged to have been signed by the Police. He also proved Exhibit PW1/3 which is a ransom note sent by NLFT and the document exhibit PW1/4 which is a subscription notice calling upon the citizens to pay subscription to NLFT. The said witness also has proved various letters being exhibits PW1/5, PW1/6 and PW1/7 issued by NLFT extremists demanding revenue and tax from different persons. Apart from these documents he had also produced a chart being exhibit PW1/9, showing

various cases registered against NLFT extremists. This chart is stated to have been prepared from the original records relating to cases registered against the activists of NLFT. The constitution of the NLFT states that the association's objective is to establish an independent identity of the Borok civilisation of Twipra after liberating "Borokland Twipra". Borok refers to the indigenous people of Tripura. PW-2 has proved various FIRs registered with Police Stations in the State of Tripura against the extremists regarding offences alleged to have been committed. PW-3 has proved the seizure of a number of arms and ammunition. The said seizure memo is Exhibit PW3/1. Ext. P.W. 3/2 is the photocopy of the letter issued by NLFT to the Commandant of 1st Bn. T.S.R. threatening to behave with Borok People of Twipra. Ext. P.W. 3/3 is the notice received for collection of revenue and tax. Ext. P.W. 3/4 and P.W. driving licence seized during the search. P.W. 4 deposed that the NLFT is also enjoying support of some of the criminals and extremists both tribals and non-tribals. Their role is that of harbourers and collaborators. He has further deposed that NLFT has certain linkages with NSCN(I) group. According to his information, NLFT has training camps and hide outs in Bangladesh. He has further deposed that NLFT by resorting to cruel methods of killing innocent people, afflicting atrocities on civilians, have tried to establish the reign of terror to prevent the civilian population to express any difference of opinion with them and also have tried to wage a war against the government established by law.

P.W. 6 was examined at New Delhi. He filed an affidavit and at the hearing proved contents thereof. He stated in his affidavit Ext. P.W. 6/1 that as a part of their secessionist aims and objectives, NLFT has prepared a separate constitution providing for a separate "People's Republic Government" with the trappings of a civilian set up. He has further stated that the NLFT has been responsible for a large number of subversive activities which include violent incidents like taking away of arms and ammunition from the para-military and the police personnel in which several Para Military/Police personnel and civilians have lost their lives. Apart from this, it continues to resort to extortion and illegal collection of money for procurement of arms and ammunition as also for maintaining its leaders and cadres. NLFT has also maintaining its leaders and cadres. NLFT has also sought to play a pivotal role in providing inspiration and support to other insurgent groups in the North East and that it has links with the NSCN(I) of Nagaland.

On behalf of the Central Government, only one witness, viz., P.W. 5 was examined at Calcutta and he has filed an affidavit by way of evidence wherein he has proved apart from other documents, the said document purporting to be the Constitution of NLFT being Ext. P.W. 5/1A which was produced by witness P.W. 5 wherefrom it appears that the NLFT's objective is to establish an independent identity of the Borok civilisation of Twipra after liberating "Borokland Twipra". From Ext. P.W. 5/1B, which is a State of Tripura's communication to the Central Government, it is clear that the NLFT headed by Biswas Mohan Debbarma has Kamini Debbarma as its self-styled Home Minister and Army Chief. Its area of operation includes areas in West Tripura, Dhalai, North and South Tripura Districts. As per the information furnished by the State of Tripura, the NLFT is in possession of twelve AK-56 Rifles, one LMG, 8 SLRs, 22 303 Rifles, one Sten Gun, 2 Pistols, 5 Revolvers and one Carbine.

It is also proved from the documents produced on record that the NLFT is mobilising its forces for increasing its secessionist, subversive and violent activities, apart from propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity. The said organisation is indulging in killings of civilians, resorting to looting, extortions, criminal acts and creation of a climate of lawlessness.

The said Act defines "unlawful activity" in Section 2(f) and "unlawful association" in Section 2(g) which read as under :—

- (f) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise).—
 - (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;
 - (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;
- (g) "unlawful association" means any association which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity."

A perusal of the evidence produced on record and the arguments advanced by the counsel for the State Government as well as Central Government proves that NLFT is engaged in subversive secessionist and violent activities and the said Association has established linkage with other unlawful associations. It is further proved that NLFT is resorting to the acts of killing of civilians and personnel belonging to police force, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring arms and ammunition by way of illegal channels and inducting them secretly in Tripura through a neighbouring country. The aims

and objects of the said NLFT are to secede from India and to establish a sovereign state of NLFT.

It is further proved on record that if NLFT is allowed to continue with its activities, it will support the insurgency and unlawful activities of the association. There is no need to discuss the contents of each of the FIRs or the affidavits or statements recorded on oath as the same form a part of the record of proceedings.

In view of the above facts and circumstances, it is proved that NLFT is engaged in various violent activities and also activities which are intended to disrupt the sovereignty and integrity of India and that with the passage of time, the unlawful activities will increase and NLFT has been advocating and practising separatism and is following secessionist policies which amount to unlawful activities as defined in Section 2(f) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

In view of the above, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) as an unlawful association. Consequently, the declaration made by the Central Government vide Notification dated 3-4-1997 under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is hereby confirmed.

Dated : 17th Sept., 1997

Nangia

J.K. MEHRA
TRIBUNAL
Unlawful Activities
(Prevention) Tribunal
New Delhi
[F. No. 9/27/97-NE-I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1997

का. आ. 799(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण
अध्यक्ष : माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. के. मेहरा

ऑल त्रिपुरा टाइनगर फोर्स (ए. टी. टी. एफ.)
के
संबंध में

न्यायाधिकरण
की रिपोर्ट

17 सितम्बर, 1997

रिपोर्ट

भारत के राजपत्र §असाधारण§ में 3 अप्रैल, 1997 को नई दिल्ली में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप §निवारण§ अधिनियम, 1967 §1967 का 37§ § जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है§ की धारा 3 की उप-धारा §i§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स §जिसे इसमें इसके बाद "प०.वि०.दे०.पफ०" कहा गया है§ को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है। उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :-

का०आ० 291 §अ§ - जबकि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स §इसके बाद इसे प०.वि०.दे०.पफ०. कहा गया है § का घोषित लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों से समझौता करके सात राज्यों यथा त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के संघ के एक पृथक राष्ट्र का निर्माण करना और इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों का भारतीय संघ से अलगाव करना और इन राज्यों को भारतीय संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखना और उसके द्वारा इन राज्यों का भारतीय संघ से अलगाव करना है,

जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि प०.वि०.दे०.पफ०. -

§i§ विध्वंसकारी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार की सत्ता को क्षति हो रही है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह लोगों में आतंक और हिंसा फैला रही है ,

§ii§ ने अन्य गैर-कानूनी संगठनों अर्थात् असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम §उल्फा§ और मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी §पी०.एल०.प०.§ से उनका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित किया है,

§iii§ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में अनेक हिंसात्मक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ है जो भारत की प्रभुता और अखण्डता के प्रतिकूल है,

और जबकि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि हिंसात्मक तथा गैर कानूनी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :-

§क§ नागरिकों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या,

§ख§ त्रिपुरा में व्यावसायिकों तथा व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन चेंठना,

§ ग § गुप्त/गैरकानूनी माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित बड़ी मात्रा में हस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त करना और उन्हें किसी पड़ोसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में गुप्त रूप से भेजना,

§ घ § सुरक्षित पनाह, प्रशिक्षण, हथियारों तथा गोलाबारूद की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी पड़ोसी देश में शिविर लगाना और उनका संचालन करना,

§ ङ § त्रिपुरा में जनजातीय तथा गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगे करवाने तथा भड़काने के लिए त्रिपुरा के अन्य जनजातीय उग्रवादी समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे बनाए रखना ।

और जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि प.दे.दे.पफ. की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए खतरा है और यह एक गैर कानूनी संगठन है,

अतएव, अब गैर कानूनी गतिविधियां § निरोधक § अधिनियम, 1967 § 1967 का 37 § की धारा 3 की उपधारा § 1 § बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पतद्द्वारा घोषणा करती है कि अंत त्रिपुरा टाइगर फोर्स § प.दे.दे.पफ. § एक गैर कानूनी संगम है,

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि प.दे.दे.पफ. पर तत्काल नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्यों के लिए अवसर मिल जाएगा -

§ i § अपने संगठनों को अलगवादी, विघटनकारी और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए संगठित करना,

§ ii § भारत की अखंडता व राष्ट्रीयता एकता के लिए हानिकर ताकतों के साथ संठ-गांठ करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुले तौर पर प्रचार करना,

§ iii § नागरिकों और पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों को लक्ष्य बनाकर हत्या करने की वारदातों में अधिकाधिक शामिल होना,

§ 11/§ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र व गोलाबारूद प्राप्त करना,

§ 1/§ अपनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी मात्रा में धनराशि पेंठना ।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का मत है कि ए0टी0टी0एफ0 को तत्काल प्रभावी रूप से गैरकानूनी संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उप-धारा 3 के पस्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्याधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

उक्त अधिसूचना का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5§ 1§ के अंतर्गत 1.5.97 को एक अधिसूचना जारी कर इस ट्रिब्यूनल का गठन किया ताकि यह न्यायनिर्णयन किया जा सके कि क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 3.4.1997 को जारी अधिसूचना द्वारा ए0आई0टी0एफ0 को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं । अधिनियम की धारा 5§ 1§ के अंतर्गत जारी दिनांक 1.5.97 की उक्त अधिसूचना इस प्रकार है :-

गृह मंत्रालय

§ फा0सं0-9/27/97-एन0ई0-1§

§ भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, धारा 3, उपधारा § 11§ में प्रकाशनार्थ§

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1997

फा0आ0 362§ अ§, -- केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप § निवारण§ अधिनियम, 1967 § 1967 का 37§ की धारा 5 की उप धारा § 1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्याय निर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि ऑल त्रिपुरा टाइनर फोर्स § ए.टी.टी.एफ. § और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा § एन0एल0एफ0टी0 को, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 3.4.1997 की अधिसूचना सं0 फा0आ0 291 § अ§ और 292 § अ§ द्वारा विधि विरुद्ध संगम

संगम घोषित किया जा चुका है, विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप § निवारण § अधिकरण" गठित करती है। अधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे०के० मेहरा से मिलकर बनेगा।

ह०/-

जी के पिल्लै

§ जी०के० पिल्लै §

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

§ फन०सं०-9/27/97-एन०ई०-1 §

इस ट्रिब्यूनल का गठन करके, ए०टी०टी०एफ० के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यकलापों का सार इस ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया है जिससे त्रिपुरा में विद्रोह की शुरुआत के संक्षिप्त इतिहास का पता चलता है। कहा गया है कि इस राज्य में जनजातीय / गैर जनजातीय तनाव का एक इतिहास रहा है। इसमें मुख्य रूप से बंगाली, त्रिपुरी, रिंग्स जमातिया और चकमा रहते हैं। कुल जनसंख्या के 31 प्रतिशत की जनसंख्या वाली जनजातियों में इस बात की शिकायत है कि पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से गैरजनजातियों के लगातार आब्रजन/घुसपैठ के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान समय में त्रिपुरा की स्थिति जनजातीय आतंकवादियों / शरारती तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हिंसा द्वारा प्रभावित है। 1993 से ही उनकी अलगवादी विध्वंसकारी और हिंसक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स § ए०टी०टी०एफ० § और दि नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा § एन०एल०एफ०टी० § अधिक सक्रिय हैं।

सार में यह भी कहा गया है कि आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जो भूतपूर्व आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का एक सहायक संगठन है, का गठन रंजीत देववर्मा द्वारा 1993 के मध्य में किया गया था। ए०टी०टी०एफ० के संविधान के अनुसार यह संगठन भारत संघ से अलग होने के पश्चात् त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नामक सात राज्यों के एक अलग राष्ट्र के गठन के लिए सशस्त्र लड़ाई को समर्थन प्रदान करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 5§1§ के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के गठन के तत्काल बाद विभिन्न समाचार पत्रों, जो त्रिपुरा राज्य में परिचालन में हैं, में प्रकाशन के जरिए प्रतिबंधित संगठन, ए०टी०टी०एफ० को नोटिस तामील किए गए थे। इस नोटिस का आकाशवाणी, अगरतला रेडियो स्टेशन से भी प्रसार किया गया था। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने अपने-अपने शपथ पत्र

वायर किए हैं जिसमें यह घोषणा की गई है कि नोटिस का अगरतला जिला, त्रिपुरा राज्य में पुलिस अधीक्षक के जरिए पुलिस द्वारा व्यापक प्रचार किए जाने के अलावा आकाशवाणी द्वारा विधिवत रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया था। हालांकि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा §2§ के अंतर्गत यथा अपेक्षित कार्य कर दिया गया था, किंतु ए.वि.वि.पफ. की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। तथापि, त्रिपुरा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया था।

नोटिस तामील हो जाने के बारे में संतुष्ट हो जाने के पश्चात्, मैंने मामले को अगरतला में राज्य सरकार का साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निर्धारित किया। राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध गतिविधियों के प्रमाण स्वरूप-दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जांच की गई गवाहियों में अधिकांशतः त्रिपुरा राज्य के पुलिस अधिकारी थे। त्रिपुरा राज्य ने कुल पांच गवाहियां अर्थात् पी.डब्ल्यू. 1 से 4 तक और पी.डब्ल्यू. 6 पेश की, पी.डब्ल्यू. 1 से 4 तक की जांच अगरतला में की गई थी जबकि पी.डब्ल्यू. 6 की जांच नई दिल्ली में की गई।

पी.डब्ल्यू. 0 1 ने कहा है कि उक्त संगठन के पड़ोसी राज्यों में अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध है। संगठन का सीमापार बंगलादेश में मुख्यालय है जहां से वह राज्य में अपनी उग्रवादी गतिविधियों को चला रहा है। उक्त गवाह ने चोबा नाक के समाचार पत्र/रसाले को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है, "संघर्ष"। उक्त रसाला पी.डब्ल्यू. -1/1 के रूप में है जिसमें इस राज्य के आदिवासियों को उत्तेजित करने वाली व्यापक सामग्री मौजूद है। पी.डब्ल्यू. 1/2 तथा पी.डब्ल्यू. 1/3 के पत्र हैं जो ए.वि.वि.पफ. से फिरौती के लिए प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त साक्ष्य में पुलिस स्टेशनों में शिकायत की गई और दर्ज की गई अनेक घटनाओं को भी सिद्ध किया गया है। अपराध शिकायत रजिस्ट्रों के सम्बद्ध उद्धरणों को पी.डब्ल्यू. 1/4 के रूप में अंकित किया गया है। साक्ष्य में आगे हत्या की घटनाओं को भी सिद्ध किया गया है। पी.डब्ल्यू. 1/5 भी एक नोटिस की प्रति है जिसमें फिरौती की मांग की गई है और ऐसा न करने पर व्यक्ति को मार दिया गया। पी.डब्ल्यू. 2 से राज्य में हो रही अपहरण की घटना सिद्ध होती है। उपर्युक्त साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि अपहरण का उद्देश्य उग्रवादियों द्वारा फिरौती की मांग करके, जैसा कि अपहृत व्यक्ति द्वारा बताया गया था, भारत संघ से अलग होने के लिए कथित स्वतंत्रता संग्राम हेतु शस्त्र इकट्ठा करना था। साक्ष्य में आगे बताया

गया है कि उनकी छानबीन से पता चलता है कि ये उग्रवदी संगठन सतछड़ी, ताराबंद §धित्तगंग§, डालुबड़ी §श्रीमंगल§ में स्थित प्रशिक्षण कैम्पों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर कैम्प उत्फा दारा नियंत्रित किए जाते हैं। पी.डब्ल्यू. -3 ने ए.टी.टी.एफ. के गठन को सिद्ध कर दिया है जो पी.डब्ल्यू. 3/1 के रूप में है। उक्त दस्तावेज भारत संघ से पृथक्ता के कारण का समर्थन करता है तथा इसकी वकालत करता है। उक्त साक्ष्य ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि ए.टी.टी.एफ. समय-समय पर ऐसे दस्तावेज प्रकाशित कर रहा है जिनमें भड़काऊ सामग्री होती है। पी.डब्ल्यू 3/2 इसी प्रकार का एक प्रकाशन है। पी.डब्ल्यू 3 करों के दारा धन एकत्र करने के लिए ए0टी0टी0एफ0 दारा जारी की गई सूचनाओं का एक नमूना है। पी.डब्ल्यू, 3/4 ए0टी0टी0एफ0 दारा जारी की गई रसीद है जिसमें करों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। साक्ष्य ने यह भी उजागर किया है कि ए.टी.टी.एफ. ने भोलेभाले लोगों की हत्या, नागरिकों पर अत्याचारों के निर्वयी तरीकों का सहारा लेकर जनता को उनकी राय से भिन्न राय प्रकट करने से रोकने के लिए आतंक की बागडोर स्थापित करने का प्रयास किया है तथा विधि दारा स्थापित सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का भी प्रयास किया है। पी.डब्ल्यू. 4 ने अपने बयान में बताया है कि सभी गैर-जनजातियों जिनके नाम 1951 की मतदाता सूची में नहीं हैं तथा जो 1949 के बाद त्रिपुरा में आए हैं, को बेदखल करने के उद्देश्य से "रखलई" §बेदखल§ नामक आंदोलन शुरू कर दिया है।

पी.डब्ल्यू. 6 से नई दिल्ली में पूछताछ की गई थी। उसने एक शपथ पत्र दायर किया था तथा सुनवाई के समय उसके तर्कों को सिद्ध किया था। उसने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 6/1 में बताया था कि उनके पृथक्तावादी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के भाग के रूप में ए.टी.टी.एफ. ने एक अलग सौवधान तैयार किया था जिसमें नागरिक ढांचे के साज-सामान के साथ एक अलग "जनगणतंत्र सरकार" की व्यवस्था की गई थी। उसने यह भी बताया है कि ए.टी.टी.एफ. अनेक विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहा है जिनमें अर्द्ध-सैनिक बलों तथा पुलिस कार्मिकों से शस्त्र एवं गोला बारूद छीनने जैसी हिंसक घटनाएं शामिल हैं जिनमें अनेक अर्द्ध-सैनिक एवं पुलिस कार्मिकों तथा नागरिकों ने अपनी जाने गवाई हैं। इसके अतिरिक्त शस्त्रों एवं गोला बारूद जुटाने के लिए तथा अपने नेताओं व संघर्षों के रख-रखाव के लिए धन पेंठने तथा धन के अवैध संग्रहण का सहारा लेता रहा है। पूर्वोत्तर में अन्य विद्रोही संगठनों को प्रेरणा एवं समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा

करना ए.टी.टी.एफ. का उद्देश्य रहा है तथा यह कि इसके अन्य प्रतिबंधित संघों अर्थात् यूनाइटेड लिब्रेशन फंड आफ असम §यू.एल.एफ.ए.§ तथा मणिपुर की प्यूफ्स लिब्रेशन आर्मी §पी.एल.ए.§ के साथ संबंध है ।

केन्द्र सरकार की ओर से केवल एक गवाह अर्थात् पी.डब्ल्यू. 5 से कलकत्ता में पूछताछ की गई थी तथा उसने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र दायर किया है जिसमें उसने अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त उक्त दस्तावेज जो कि ए.टी.टी.एफ. के संविधान से संबंधित है जो कि पी.डब्ल्यू. 5 /1ए §संयुक्त रूप से§ है जिसे गवाह पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत संघ से अलग होने के बाव त्रिपुरा असम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश सात राज्यों को मिला कर एक अलग राज्य के गठन के लिए ए.टी.टी.एफ. सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करता है । उसने यह भी बताया है कि अध्यक्ष तथा संघ के वारिष्ठ सदस्यों की केन्द्रीय समिति के अतिरिक्त ए.टी.टी.एफ. की 2 सशस्त्र रेजीमेंट हैं अर्थात् बीर विक्रम रेजीमेंट और बोरोक रेजीमेंट । यह स्पष्ट है कि ए.टी.टी.एफ. के मुखिया रंजीत देववर्मा हैं । इसके प्रचालन क्षेत्र में पश्चिम त्रिपुरा दलाई उत्तरी एवं दक्षिणी त्रिपुरा जिले शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य में प्रदत्त सूचनानुसार ए.टी.टी.एफ. के पास 135/140 ए के-56 राइफलों, 15/16 ए के-47 राइफलों, ग्यारह 303 राइफलों, दो एल.एम.जी. 3 रिवाल्वर, 3 पिस्तौल और दो कार्बाइन हैं । यह इससे भी सिद्ध होता है कि ए.टी.टी.एफ. ने आप्रवासी बंगाली स्थापितों को त्रिपुरा से निकालने की मांग की है ।

रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह सिद्ध होता है कि भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की विरोधी ताकतों के सहयोग से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करने के अलावा ए.टी.टी.एफ. अलगाववादी, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है । उक्त संगठन नागरिकों की हत्याओं, लूटपाट, छीनाछपट, आपराधिक कार्य और कानून विहीनता का वातावरण बनाने में संलिप्त है ।

उक्त अधिनियम में धारा 2(च) में "विधि विरुद्ध गतिविधि" और धारा 2 (छ) में "विधि विरुद्ध संगम" की परिभाषा दी गई है जो कि इस प्रकार है :-

§ च § किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में "विधि विरुद्ध गतिविधि" का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा की गई कोई ऐसी कार्रवाई से है § कोई कार्य करके या बोले गये या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या प्रकट कार्यकलापों या अन्य प्रकार से §

§ i § जो भारतीय क्षेत्र के किसी भाग के अलगाव या भारत संघ से उनके किसी भाग के अलगाव का किसी भी आधार पर झूठ है या समर्थन करता है अथवा जो ऐसे अलगाव के लिए व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उकसाता है,

§ ii § जो भारत की सम्प्रभुता एवं भूभागीय अखण्डता को नहीं मानता है, सवाल उठाता है, पृ. छिन्न-भिन्न करता है या छिन्न-भिन्न करना चाहता है,"

§ iii § "विधिविरुद्ध संगम" का अर्थ है - ऐसा संगम जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विधिविरुद्ध कार्य करता है, या जो विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों को उकसाता या उनकी मदद करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसे कार्य करते रहते हैं ।"

रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारता की दलीलों से यह सिद्ध होता है कि ए.टी.टी.एफ. विध्वंसक, अलगाववादी व हिंसक गतिविधियों में संलग्न है और उक्त संगम ने दूसरे विधिविरुद्ध संगमों से भी अपने संपर्क बनाये हैं । यह भी सिद्ध होता है कि ए.टी.टी.एफ. नागरिकों और पुलिस बलों के कार्मिकों की हत्याओं और अवैध माध्यमों से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने तथा उनको एक पड़ोसी देश के रास्ते गुप्त ढंग से त्रिपुरा लाने के लिए त्रिपुरा की जनता एवं व्यापारियों से धन पेंठने के कार्य करती रही है । उक्त संगम का उद्देश्य एवं लक्ष्य भारत से अलग होना तथा ए.टी.टी.एफ. का एक सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य स्थापित करना है । रिकार्ड से यह भी सिद्ध होता है कि यदि उक्त गतिविधियां जारी रखने की ए.टी.टी.एफ. को अनुमति दी जाती रही तो इसका अर्थ होगा उसकी विद्रोही एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों को समर्थन देना । प्रत्येक एफ.आई.आर. या शपथ में रिकार्ड किए गए प्रत्येक हलफनामों पर पूर्णतः विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कार्यवाही रिकार्ड का ही भाग हैं।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह सिद्ध हो जाता है कि ए. टी. टी. एफ. विभिन्न हिंसक गतिविधियों में और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जिनसे भारत की संप्रभुता और अखण्डता के छिन्न-भिन्न होने का खतरा है। यह भी सिद्ध होता है कि समय बीतने के साथ-साथ विधिविरुद्ध गतिविधियां बढ़ती जाएंगी और ए. टी. टी. एफ. अलगाववाद की वकालत करता रहा है और अलगाववादी नीतियां अपना रहा है जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(च) में परिभाषितानुसार विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को बढ़ाती है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं संतुष्ट हूँ कि आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए. टी. टी. एफ.) को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं। परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार सरकार द्वारा दिनांक 3-4-97 की अधिसूचना के द्वारा घोषणा की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

दिनांक 17 सितम्बर, 1997

नांगिया

(जे. के. मेहरा)

ट्रिब्यूनल

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) न्यायाधिकरण

नई दिल्ली।

[फा. सं. 9/27/97-एन. ई. I]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1997

S.O. 799(E).—The following is published for general information :—

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

HEADED BY HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MEHRA

IN THE MATTER OF

ALL TRIPURA TIGER FORCE (ATTF)

REPORT OF THE TRIBUNAL

17th September, 1997

REPORT

By a Notification of Ministry of Home Affairs published at New Delhi on 3rd April 1997 in the Gazette of India (Extraordinary), the Central Government in the exercise of its powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act), declared the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as "ATTF") as an unlawful association. The said notification reads as under :—

S.O. 291(E).—Whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region and to carry on armed struggle for separation of these States from the Indian Union and thereby secession of these States from Indian Union:

And whereas the Central Government is of the opinion that ATTF has—

- (i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the lawfully established Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;
- (ii) established linkages with other unlawful associations, viz., United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam and the People's Liberation Army (PLA) of Manipur with the aim of mobilising their support;
- (iii) in pursuance of its aim objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas the Central Government is further of the opinion that violent and unlawful activities include—

- (a) killing of civilians and personnel belonging to the Police Security Forces;
- (b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;
- (c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;
- (d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition, etc.;
- (e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

And whereas the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) the Central Government hereby declares the All Tripura Tiger Force (ATTF) as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the ATTF will take the opportunity to—

- (i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;
- (ii) openly propagate anti-national activities in collusion, with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in increased killings of civilian and targeting of police and Security Forces Personnel;
- (iv) Procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;
- (v) extort and collect huge funds from the public for its activities;

Having regard to the above circumstances, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the ATTF as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section 3 of the said section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Following the said Notification, Government of India issued a Notification dated 1-5-97 under section 5(1) of the said Act constituting this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the ATTF, unlawful association declared as such by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S.O. 291(E) dated 3-4-1997. The said Notification dated 1-5-97 issued under Section 5(1) of the Act reads as under :—

Ministry of Home Affairs

(F. No. 9/27/97-NE. I)

(TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY)

Government of India

Ministry of Home Affairs

Notification

New Delhi, dated the 1st May, 97

S.O. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force (ATTF) and National liberation Front of Tripura (NLFT) as unlawful associations declared as such by the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S.O. 291(E) and 292(E) dated 3-4-1997 respectively. The Tribunal shall consist of Mr. Justice J.K. Mehra Judge of the Delhi High Court.

Sd/-

G. K. PILLAI, Jt. Secy. to the Govt. of India.

[F. No. 9/27/97-NE. I]

With the constitution of this Tribunal, the resume on the aims, objectives and activities of ATTF has also been filed before this Tribunal which gives brief history of the origin of the insurgency in the State of Tripura. It is stated that the State, which has a history of tribal/non-tribal tension, is mainly inhabited by Bengalis, Tripuras, Reangs, Jamatias and the Chakmas. The tribals, who comprise approximately 31% of the total population, harbour a grievance of being overwhelmed by non-tribals through successive waves of migration/infiltration from neighbouring East Pakistan/Bangladesh. It is further mentioned that currently in Tripura the situation is affected by a high level of violence by tribal extremists/miscreants. Their secessionist, subversive and violent activities have been on the increase since 1993. The All Tripura Tiger Force (ATTF) and the National Liberation Front of Tripura (NLFT) are the most active.

It is further submitted in the resume that the All Tripura Tiger Force, which is an offshoot of the erstwhile All Tripura Tribal Force, was formed in mid-1993 by Ranjit Debbarma. As per the ATTF's constitution, the outfit supports an armed struggle for formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh after seceding from the Indian Union.

Immediately on being constituted the Tribunal under Section 5(1) of the said Act, notices were served upon the ATTF, the banned organisation by way of publication in various newspapers which are in circulation in the State of Tripura. The notice was also broadcast by the AIR from Agartala Radio station. Central Government and State Government have filed their respective affidavits declaring that the notices were duly published and broadcast by AIR in addition to wide publicity to notice by Police through Superintendent of Police in the District of Agartala, State of Tripura. Although service was effected as required under sub-section (2) of Section 4 of the Act, no one put in appearance on behalf of ATTF. The State of Tripura and Central Government were, however, represented.

After feeling satisfied about service of notices, I fixed the case for recording evidence of the State Government at Agartala. Documentary as well as oral evidence has been produced by the State Government in proof of the activities listed in the aforesaid notification. Most of the witnesses examined were the police officers from the State of Tripura. State of Tripura produced in all five witnesses being p.w. 1 to 4 and P.W. 6. P.W. 1 to 4 were examined at Agartala, while P.W. 6 was examined at New Delhi.

PW-1 has stated that the said organisation has links with other terrorist organisations in the the neighbouring states. The organisation is having its heardquarter across the border in Bangla Desh wherefrom it is directing its militant activities in the State. The said witness also proved a newspaper/magazine named Choba which in the local language means 'struggle'. The said magazine is exhibit PW-1/1 which contains inflammatory material with a view to incite the tribals of this State. Exhibits

PW-1/2 and PW-1/3 are the communication received for ransom from ATTF. The said witness has also proved a number of incidents complained of and registered with police stations. The relevant extracts of the crime complaint registers is marked as exhibit PW-1/4. The witness has further proved the killing incidence also. Exhibit PW-1/5 is also a copy of the notice demanding ransom, failing to comply with the same the man was killed. PW-2 has proved the kidnapping incidence happening in the State. The said witness has further stated that the object of kidnapping was claiming ransom by the extremists, as disclosed by the kidnapped person, was acquisition of arms to carry on the alleged independence struggle to secede from Indian Union. The witness has further stated that their investigations had revealed that these extremists outfits are getting training at training camps situated at Satchari, Taraband (Chittagang), Dalubari (Srimangal) and Vishwamani in Bangla Desh. Most of these centres are controlled by ULFA. PW-3 has proved the constitution of ATTF which is marked as exhibit PW-3/1. The said document supports and advocates the cause of secession from Indian Union. The said witness has further proved that ATTF has been publishing documents from time to time containing inflammatory material. Exhibit PW-3/2 is one such publication. Exhibit PW-3/3 is a specimen of notices issued by ATTF for collecting money by way of taxes. Exhibit PW-3/4 is a receipt issued by ATTF acknowledge receipt of taxes. The witness has further disclosed that ATTF by resorting to cruel methods of killing innocent people, afflicting atrocities on civilians, have tried to establish the reign of terror to prevent the civilian population to express any difference of opinion with them and also have tried to wage a war against the government established by law. PW-4 has stated in his statement that ATTF has started a movement called 'Rakhlai' (oust) with object to oust all non-tribals whose names are not borne on the voters list of 1951 and have entered Tripura after 1949.

PW-6 was examined at New Delhi. He filed an affidavit and at the hearing proved contents thereof. He stated in his affidavit exhibit PW-6/1 that as a part of their secessionist aims and objectives, ATTF has prepared a separate constitution providing for a separate "People's Republic government" with the trappings of a civilian set up. He has further stated that the ATTF has been responsible for a large number of subversive activities which include violent incidents like taking away of arms and ammunition from the para-military and the police personnel in which several para Military/Police personnel and civilians have lost their lives. Apart from this, it continues to resort to extortion and illegal collection of money for procurement of arms and ammunition as also for maintaining its leaders and cadres. ATTF has also sought to play a pivotal role in providing inspiration and support to other insurgent groups in the North East and that it has links with other banned Associations viz. United Liberation Front of Asom (ULFA) and the People's Liberation Army (PLA) of Manipur.

On behalf of the Central Government, only one witness, viz., P.W. 5 was examined at Calcutta and he has filed an affidavit by way of evidence wherein he has proved apart from other documents, the said document purporting to be the Constitution of ATTF being Ext. P. W. 5/1A (Collectively) which was produced by witness P.W. 5 wherefrom it appears that the ATTF supports an armed struggle for formation of a separate nation of seven sister comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh after seceding from the Indian Union. He has further stated that besides a Central Committee comprising the President and senior members of the Association, the ATTF have two armed regiments, viz., Bir Bikram Regiment and Borok Regiment. It is clear that the ATTF is headed by Ranjit Debbarma. Its area of operation includes areas in West Tripura, Dhalai, North and South Tripura Districts. As per the information furnished by the state of Tripura, the ATTF is in possession of 135/140 AK-56 Rifles, 15/16 AK-47 Rifles, eleven 303 Rifles, two LMG, 3 Revolvers 3 Pistols and two Carbine. This witness has further stated that the ATTF has demanded expulsion of immigrant Bengali settlers from Tripura.

It is also proved from the documents produced on record that the ATTF is mobilising its forces for increasing its secessionist, subversive and violent activities, apart from propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity. The said organisation is indulging in killings of civilians, resorting to looting, extortions, criminal acts and creation of a climate of lawlessness.

The said Act defines "unlawful activity" in section 2 (F) and "association" in Section 2 (g) which read as under :—

(f) "unlawful activity" in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

(g) "unlawful association" means any association which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity."

A perusal of the evidence produced on record and the arguments advanced by the counsel for the State Government as well as Central Government prove that ATTF is engaged in subversive secessionist and violent activities and the said Association has established linkage with other unlawful associations. It is further proved that ATTF is resorting to the acts of killing of civilians and personnel belonging to police force, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring arms and ammunition by way of illegal channels and inducting them secretly in Tripura through a neighbouring country. The aims and objects of the said ATTF are to secede from India and to establish a sovereign state of ATTF. It is further proved on record that if ATTF is allowed to continue with its activities, it will support the insurgency and unlawful activities of the association. There is no need to discuss the contents of each of the FIRs or the affidavits or statements recorded on oath as the same form a part of the record of proceedings.

In view of the above facts and circumstances, it is proved that ATTF is engaged in various violent activities and also activities which are intended to disrupt the sovereignty and integrity of India and that with the passage of time, the unlawful activities will increase and ATTF has been advocating and practising separatism and is following secessionist policies which amount to unlawful activities as defined in Section 2(f) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

In view of the above, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force (ATTF) as an unlawful association. Consequently, the declaration made by the Central Government vide Notification dated 3-4-1997 under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is hereby confirmed.

Date: 17th Sept., 1997
Nangia

(J. K. MEHRA)
TRIBUNAL
Unlawful Activities
(Prevention) Tribunal
New Delhi.

[F.No. 9/27/97-NE. I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy

